मोदी की चर्चा भारत से अमेरिका तक –

अभी चुनावों को लगभग एक वर्ष बचा हुआ है, किन्तु नरेन्द्र मोदी हॉ या ना को चर्चा सम्पूर्ण भारत में प्रतिदिन होती रहती है। आश्चर्य हुआ, जब भारत की यह चर्चा अमेरिका तक पहुॅचा दी गयी । भारतीय जनता पार्टी आन्तरिक रुप से पूॅजीवाद की पक्षधर है। किन्तु प्रत्यक्ष रुप से हमेशा ही अमेरिका या ब्रिटेन के विरुद्ध दिखना चाहती है। पिछले नौ वर्षो के कांग्रेसी शासन काल में एक भी ऐसा अवसर नही आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी रुप मे अमेरिका की पक्षधर दिखी हो या कम से कम तटस्थ दिखो हो। मनमोहन सिंह की सरकार ने कभी ऐसा नाटक नही किया। उसने हमेशा ही स्वयं को अमेरिका के पक्ष में दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह को इसी आरोप में घेरने की कोशिश की कि वे अमेंरिका के पक्षधर है। साम्यवादियों ने भी कभी ऐसा नाटक नही किया जिसमें वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका के समर्थन मे रहे हो या दिखे हा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही अपना दोहरा चरि़त्र दिखाया। उसने तो मनमोहन सरकार को गिराने के लिये अमेरिका विरोध नाम पर साम्यवादियों तक से हाथ मिला लिया। इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी से लेकर एक साधारण कार्यकर्ता तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का निरंतर विरोध करते दिखते है। यहॉ तक कि विरोध करते–करते ये तो तोड़फोड़ तक उतर जाते है। नाटक के प्रत्यक्ष स्वरुप में ऐसा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अन्दर से बाहर तक अमेरिका के विरुद्ध है। उसी भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को अमेरिका ने अमेरिका आने का विजा देने से इन्कार कर दिया तो नरेन्द्र मोदी तक ने अमेरिकी सांसदो की अन्दर –अन्दर खुशामद शुरु कर दी। हद तो तब हुयी जब भारतोय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका जाकर वहॉ के राष्ट्रपति ओबामा से होने वाली चर्चाओं में इस निवेदन को शामिल करना उचित समझा कि अमेरिका मोदी को अमेरिका आने का विजा देने पर विचार करें। इस निवेदन में राजनाथ सिंह जी को न भारत को राष्ट्रीयता का अपमान दिखा न भारत के स्वाभिमान का न अपने अमरिका विरोधी चेहरे की नकाब उतरने का । यह बात अमेरिका में न कहकर भारत से मजबूती के साथ कही जाती तब उतना बुरा नही था। जितना अमेरिका जाकर अमेरिकी प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाने का । इस प्रसंग ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुॅचाया है।

किन्तु यह बोमारी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा नही है। भारत के 65 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर अमेरिका से गुप्त रुप से निवेदन किया कि मोदी को अमेरिका का विजा न दिया जाय। ऐसे मोदी विरोधी पत्र का नेतत्व एक मुस्लिम सांसद ने किया। एक ऐसे सांसद न ऐसे लोगो के हस्ताक्षर करवाएॅ जो आमतौर पर अमेरिका विरोधी जाने जाते है। यहॉ तक कि उसमें साम्यवादी नेता सोताराम येचुरी तक के हस्ताक्षर का दावा किया गया। सोताराम येचुरी मोदी विरोधी होने की अपेक्षा अमेरिका विरोधी अधिक जाने जाते है दूसरी ओर तथाकथित मुस्लिम सांसद भी ये दावा करते है कि वे अमेरिका विरोधी है। ऐसे अमेरिका विरोधी सांसदों द्वारा अमेरिका से इस प्रकार निवेदन करना इनकी पोल खोलता है। चिठ्ठी गुप्त से लिखी गयी थी, लेकिन प्रत्यक्ष हो गयी तो अब ये अमेरिका विरोध का नाटक करने वाले अपनी –अपनी सफाई के लिए कह रहे है कि उनके हस्ताक्षर जालो है। हस्ताक्षर कराने वाले अब भी दावा कर रहे है कि उनके हस्ताक्षर असली है और ये सांसद सफाई दे रहे है कि हस्ताक्षर नकली है। सब जानते है कि भारत में नकली हस्ताक्षर करना या हस्ताक्षर करके इन्कार कर देना संप्रभु सांसदों के लिए किसी तरह खतरें की घंटी नही है। चाहे नकली हो या असली लेकिन ये सांसद जनता की नजरो से बेदाग नही बच सकते। वे तो बिल्कुल नही जिन्होंने अमेरिका विरोंधी होते हुये ये हस्ताक्षर कराकर अमेरिका से निवेदन किया।

भारत में सम्मानित विद्वान अमत्य सेन ने अपना मत व्यक्त किया कि नरेंन्द्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नही होना चाहिए । मैं अमत्य सेन क विचारों का पक्षधर या प्रशंसक कभी नही रहा हूॅ। किन्तु जिस भाषा में अमत्य सेन को मोदी सर्मथको ने उत्तर दिया वह उत्तर पूरी तरह इनके दिवालियॉ पन का सबूत है। क्या मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले ही इस तरह की दादागिरी मोदी को प्रधानमंत्री बनने में सहायक होगी ? क्या गुजरात में ऐसी ही दादागिरी के बल पर चुनाव जीते गये।यदि ऐसा हुआ तो गुजरात के जीते गये चुनाव भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं नरेन्द्र मोदी का प्रशंसक इसलिए रहा कि नरेन्द्र मोदी ने उच्श्रृखंलता पर लगाम लगायी किन्तु यदि मेरे मन में जरा भी यह भाव पैदा हुआ कि यह उच्श्रृंखलता मोदी समर्थको की उच्श्रृखलता में सहायक है तो मैं अपने अब तक के एकपक्षीय मोदी सर्मथन के लिए देश से क्षमा मॉग लूॅगा। अमर्त्य सन ने जो कहॉ वह अभिव्यक्ति की सोमाओं के अन्दर था। अभिव्यक्ति की आजादी को गुण्ड़ागर्दी से दबाने का यह संघ परिवार का पहला उदाहरण नही है। गुजरात के चुनाव में भी मेघा पाटकर के साथ तथा कुछ अन्य गॉधीवादियों के साथ ऐसा व्यवहार हो चुका है। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में जिस तरह मुस्लिम संगठनों का घमंड़ चकनाचूर किया उसने मोदी को इतना आगे बढ़ा दिया। इसका यह अर्थ नही है कि मुस्लिम गुण्ड़ों की जगह अब हिन्दू गुण्ड़े ले लेंगे। जिस तरह एक भाजपा नेता ने चुनाव बाद उनका पदक छीन लेने को धमकी दी अथवा कुछ तथाकथित मोदी प्रशंसकों ने अमर्त्य सेन की फिल्मी लड़की का चरित्र हनन करना शुरु किया यह तो देश के लिए सम्पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बड़े खतरें के रुप में है। यदि

ऐसी गुण्ड़ागर्दी जारी रहती है तो अमर्त्य सेन से आगे बढ़कर मैं ऐसे मोदो समर्थक गुण्ड़ा का विरोध करूॅगा। मोदी जो को स्वंय आगे आकर इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहिए था जो उन्होने न कहकर एक भूल को है।

भारतीय जनता पार्टी के अन्दर भी कुछ उथल पुथल जारी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के नाम पर मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया । मध्यप्रदेश के चुनाव में वे मोदी को छोड़कर अन्य राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं के नाम का उपयोग कर रहे है। किन्तु मोदी के नाम से परहेज कर रहे है। अभी एक सर्वेक्षण में भी यह बात सामने आयी है कि शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में मोदी से बहुत आगे है। उसी तरह जिस तरह गुजरात में नरेन्द्र मोदी । इसलिए संभव है कि शिवराज सिंह चौहान में भी महत्वाकांक्षा जगी हो अथवा उन्हें नरेन्द्र मोदी में कुछ लोकतांत्रिक विचारों की कमी दिखती हो ।

जो भी हो सारे देश का राजनैतिक वातावरण मोदी के पक्ष और विपक्ष पर आकर सिमट गया है। इस चर्चा में सबसे अधिक मोदी के विरोध में मुस्लिम धर्म प्रमुखों अथवा मुस्लिम राजनेताओं की उछलकूद दिखती है। अभी –अभी बाटला हाउस इन्काउटर के न्यायिक नतीजें सामने आये और इसके बाद भी हमारी कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को शर्म महसूस नही हुयी जो इस इन्काउन्टर को फर्जी करार दे रहे थे। आज भी अनेक निर्लज टी0 बी0 पर आकर उस आतंकवादी को निर्दोष कहते रहते है। आतंकवादी के वकील उसके परिवार के लोग अथवा कुछ इष्ट मित्र उसे निर्दोष कहे तो बात समझ में आती है। यदि उसके संगठन के साथी भी इसे निर्दोष कहे तो ऐसे कहने वालो को क्षमा किया जा सकता है। किन्तु यदि कुछ अपवादों को छोंड़कर आम मुसलमान उसके पक्ष में आवाज उठाने लगे तो ऐसा महसूस होता है कि आज देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि अधिकांश आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते है। तथा ऐसे आतंकवादी को पहचानते समय निर्दोष मुसलमाना से भी पूछताछ की जाये तो इसस आम मुसलमानों को कष्ट क्यों होता है? भारत के आम मुसलमानों को यह साफ कहना होगा कि वे आतंकवाद विरोधी सरकारी गतिविधियों के समर्थक है, तटस्थ समोक्षक है, या विरोधी? यदि वे विरोधी है तो नरेन्द्र मोदी सरोखे किसी समाधान की आवश्यकता महसूस होती है। वाटला हाउस इन्काउन्टर में आम मुसलमानों की भूमिका न प्रसंशक की रही है, न तटस्थ समोक्षक की बल्कि वह तो आतंकवाद समर्थक की हो ज्यादा दिखी है। यदि आतंकवादियो मे 90 प्रतिशत तक मुसलमानों को संख्या है तो जेलों में बंद परोक्षण कालोन संदेहास्पद आतंकवादी नागरिको में से भी निर्दोष मुसलमानों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है। नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से यदि कोई रोक सकेगा तो वह है एक मात्र नरेन्द्र मोदी की तानाशाही का आभास और यदि नरेन्द्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री बना सकेगा तो वह है मुसलमानो का विरोध में बढ़ चढकर हिस्सा लेना । आज नरेन्द्र मोदी के मामले में मैं स्पष्ट हूॅ कि नरेन्द्र मोदी का चुनाव जोतना देश की आवश्यकता है क्योंकि देश में संगठित गिरोंहो पर लगाम लगाने वाला कोई नही दिखता है। दूसरी ओर मैं यह भी स्पष्ट हूॅ कि नरेन्द्र मोदी के चुनाव जोतने का अर्थ है भारत में भविष्य में कभी चुनाव नही होने तक को सभावनाओ का खतरा । यदि हमारे समक्ष इस्लामिक उच्श्रृखलता तथा अपराध वृद्धि के निवारण का समाधान दिखता है तो दूसरी ओर हिन्दुत्व के नाम पर बढती उच्श्रृखलता का खतरा भी। हमारे सामने तानाशाही और सुव्यवस्था के बीच कोई एक मार्ग चुनने का संकट आ पड़ा है।

फिर भी सब कुछ होते हुए भी मोदी पक्ष विपक्ष भारत का आंतरिक मामला हैं, जिसे हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे ।, किन्तु इस मामले को अमेरिका में उठाकर राजनाथ सिंह जी अथवा 65 सांसदो ने जो भूल की है वह कोई साधारण अपराध नही है। इसकी गंभीरता हमारे लिए चिंता का विषय है और भारत के लोगों को इस बात से खुश होना चाहिए कि अमेंरिका विरोधियों के चेहरे का नकाब हट रहा है।

प्रश्नोत्तर

1 श्री छवील सिंह सिसोदिया उपाध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच

प्रश्न– ज्ञान तत्व दो सौ सत्तर मे आपने न्यायिक सक्रियता पर प्रश्न उठाया हैं । विचार करिये कि यदि विधायिका समाज की समस्याएं हल न करे तो क्या न्यायालय भी चुपचाप बैठा देखता रहें। जब विधायिका उच्श्रखल होती है तभी तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मेरे विचार से विधायिका का मनोबल बढाना ठीक नही।

उत्तर– विधायिका गलत है तभी तो न्यायापालिका के असंवैधानिक कदमों को भी पूरा–पूरा जन सर्मथन मिला। इस जन सर्मथन को न्यायापालिका ने अपना सर्मथन मान लिया जो गलत था। जन समर्थन विधायिका के विरुद्ध था न कि न्यायालय का समर्थन।

आपका यह कथन तो बिल्कुल उल्टा है कि समाज की समस्याए यदि कानून हल न कर सके तो न्यायालय हल करेगा। यह तो सम्भव ही नही है। न कानून से समाज की समस्याएँ हल हो सकती हैं न न्यायालय से । विधायिका और न्यायालय यदि अपनी समस्याएँ हल नही कर सकेंगे तब उनकी समस्या समाज हल करेगा । समाज सर्वोच्च है। कानून का काम है व्यक्ति की उच्श्रृंखलता को रोकना न कि समाज की स्वतंत्रता मे दखल देना। यही उसकी अंतिम सीमा भी है। यदि विधायिका इस काम को न करे तो न्यायालय इसके लिये पहल कर सकता है ।

न्यायालय का काम है कि किसी नीचे की इकाई को उपर की इकाई दबा न सके। यदि समाज व्यक्ति के चार मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करें तभी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है अन्यथा नही। समाज के समाजिक मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नही कर सकता । समाज न्यायालय से उपर होता है न कि नीचे । यदि विधायिका उत्श्रृंखल हो तो न्यायालय को चाहिये कि वह विधायिका का नियंत्रित करें। यह कार्य न्यायापालिका का न होकर उसका अतिरिक्त कार्य है। उसी तरह यदि न्यायापालिका को विधायिका पर अंकुश लगाने को आदत पड़ जाये तो विधायिका का भी काम है कि वह न्यायापालिका के कान मरोंड़े । अब भी संतुलन विधायिका के विरुद्ध न्यायापालिका के पक्ष में ही ज्यादा झुका हुआ है । अपराधियो और राजनीति के संबंधो के मामले मे विधायिका द्वारा उठाये जा रहे कदमो ने यह संतुलन और भी अधिक विधायिका के विरूद्ध झुका दिया है, किन्तु न्यायपालिका को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

जिस समय भारत में प्रधानमंत्री मजबूत थे तथा प्रधानमंत्री का संसद में प्रबल बहुमत था उस समय न्यायापालिका को मजबूत होना चाहिये अन्यथा विधायिका मनमानी करने लगेगी। इस समय तो प्रधानमंत्री भी बेहद कमजोर है तथा उनका बहुमत भी नही के बराबर है तब न्यायापालिका को इतना सक्रिय क्यों हाना चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं न्यायापालिका को भी खोजना चाहिये।

2 श्री शिवदत्त, बांदा, उत्तरप्रदेश

प्रश्न– नदी जब उफान मे (अति) होती है तो डरावनी लगती है। जब वही नदी सामान्य गति से बहती है तो सुहावनी लगती है, नजदीक जाने का मन करता है। आज आदमी भी अतियों मे जी रहा है और डरावना बन गया है। इस स्थिति के लिये वह कतई दोषो नहीं है। अति को परिस्थितियां पैदा करने वालो ने ऐसे ऐसे जाल आदमी को फसाने के लिये बुने है जिसमे पडकर उसकी सामान्य गति का लोप हो गया है। मुफत खोर और शोषक जाल मे फसे आदमी के लिये उपदेश कर रहे है, किताबें पोथियां लिख रहे है, लिखे जा रहे हैं, और इसी पर वाह वाही लूट रहे है, अपनी पूजा करा रहे है, तथा विद्वान और विचारक कहला रहे है। उपदेश देने की बीमारी कुछ को पहले से थी पर वे किसे उपदेश करे? जब कोई असामान्य स्थितियों मे हो तभी उसे उपदेश किया जा सकता है। ये मुफतखोर उपदेशक समाज मे सामान्य स्थिति पैदा होने देने तथा मनुष्य की सामान्य गति की राह मे बाधक है। क्योकि तब इनका धंधा चौपट हो जायगा। अनुशासन सृष्टि का आधार है। सूरज एक निश्चित समय मे आता है, एक निश्चित समय मे जाता है। मधु मक्खियां अनुशासित रहकर ही मधु संग्रह करती है। अनुशासन का मतलब स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण। यह दूसरो के अधिकारों की स्वतंत्रता का रक्षक है। अनुशासन विहीन इंसानी समाज की कल्पना की जा सकती है क्या? बैलगाडी का एक बैल इधर एक बैल उपर खीचे तो गंतब्य मुश्किल है। करोडों करोडों वर्षो से इन्ही विचारों विवादो मे आदमी उलझा हुआ है और अपनी सामान्य गति पाने के लिये तरस रहा है। वह सबकी पूजा अर्चना करते करते सबकी सुनते सुनते थक चुका है पर आज तक अपनी स्थिति उसे नही मिल पाई। राम राज्य मे कोई लिखित कागजी संविधान था क्या? पर वह दुनियां की सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था थी जिसका सपना गांधी ने आज के संदर्भ मे भारत के लिये देखा था। कागज मे लिखी लाइनो की घुटटी किसी को पिला देने से नीयत का नही बांधा जा सकता। आदमी को आदमी होना चाहिये। तब किसी लिखित राजनीतिक दस्तावेज की जरूरत नही है। इस देश की मूल समस्याा है नाम परिवर्तन की उस पर कोई विचारक विद्वान विचार नही कर रहा है। क्या आप भारत के इंडिया नाम से सहमत हैं?

उत्तर– उपदेश और प्रवचन में आसमान,पाताल जैसा अन्तर होता है।

उपदेश पूरी तरह सत्य,तत्व,कथनी और करनी की एकरुपता ,मस्तिष्क ग्राहय ,विचार प्रधान तथा अपने स्वतः के ज्ञान से ओत–प्रोत होता है।

प्रवचन बंधन रहित ,हृदय ग्राहय ,कला प्रधान ,शिक्षा से ओत–प्रोत तथा कथनी करनी की एकरूपता का होता है।

भाषण बंधन रहित ,हृदय ग्राहय ,कला प्रधान ,ज्ञान शिक्षा मुक्त ,कथनी करनी की एकरुपता से मुक्त होता है।

शिक्षा तत्व और कला के बंधन से मुक्त,हृदय और मस्तिष्क का समन्वय ,सत्य असत्य बंधन मुक्त ,आचरण से मुक्त, दूसरों के विचार होते है। शिक्षा में न सत्य असत्य का बंधन है न आचरण की आवश्यकता न ज्ञान से संबंध। शिक्षा दूसरों के विचार दूसरो तक पहुचाने के माध्यम तक सीमित हैं।

आप जिन्हें उपदेशक कहते हैं वे या तो प्रवचन कर्ता हैं या शिक्षा देने वाले। उपदेश देना बहुत कठिन कार्य है और उपदेश सुनना तो और भी कठिन है क्योंकि न उपदेश का कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है न श्रोता को मजा आता है।यही कारण है कि उपदेश की लाइन में बिरले ही निकल पाते हैं। फिर उपदेशक अपने आचरण में भी असत्य का सहारा नही ले सकता न ही अपने प्रवचन में असत्य बोल पाता है। बाबा रामदेव तो अब प्रवचन या शिक्षा से भी नीचे उतर कर भाषण देने लगें है। इस निमित्त आपको दुखी नही होना चाहिये। उपदेशक के रुप में वर्तमान में अन्ना हजारे को माना जा सकता है। आपने देश के नाम की चिन्ता की । मेरा विषय देश या राष्ट्र की सीमाओं से उपर उठकर समाज की सीमाओं तक का है जिसमें न कही इण्डिया है न ही भारत । मेरो अपनी सीमाएं है । मेरी अपनी क्षमता है। मै न अपनी क्षमता से बाहर जाना उचित समझता हूँ न अपनी सीमाओ से । इसी लिये मै इंडिया और भारत जैसे विषयो से दूर रहता हूँ।

3 ह्षिकेष मिश्र,बिल्थरा रोड, मउ,उत्तरप्रदेश

प्रश्न– ज्ञानतत्व मिलता है। कुछ प्रश्न उभरते हैं

(1) क्या बिना सत्ता परिवर्तन के व्यवस्था परिर्वतन संभव है? क्या वर्तमान चुनाव प्रणाली में यह सम्भव है?

(2) यह सच है कि देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अरविन्द जी का दल भ्रष्टाचार दूर करने के उद्देश्य से ही चुनावों में कूदा है। आपको कैसी संभावना दिखती है?

(3)अन्ना हजारें ,स्वामी रामदेव तथा अरविन्द केजरीवाल लगातार अच्छे लोगों को जिताने की बात कर रहे हैं। अच्छे की पहचान क्या है तथा क्या उनका जोतना संभव है?

(4) संविधान में दस वर्षों के लिये आरक्षण था जिसे लगातार बढ़ाया गया। क्या यह उचित है?

(5)राइट टू रिजेक्ट या राइट टू रिकाल जैसी बातें वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था नहीं मानती। हल क्या है?

उत्तर– सत्ता अलग होती है और संसद अलग । संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है। इसके समाधान के दो मार्ग हैं (1)संसद में जाकर संविधान संशोधन । (2) प्रबल जनमत जागृत करके वर्तमान संसद को संविधान संशोधन के असीम अधिकारों में कटौती हेतु तैयार करना। अन्य कोई मार्ग न सम्भव है न उचित। हम दोनों दिशाओं में प्रयत्न कर रहे है। हम संविधान संशोधन का विस्तृत प्रारुप भी जनमत में प्रसारित कर रहे है तथा लोक संसद के मुद्दे पर प्रबल जनमत खड़ा करके वर्तमान संसद पर एक दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अरविन्द केजरीवाल ने लोक संसद के सुझाव को सिरे से नकार दिया और मैने लोकपाल को अपर्याप्त माना। अन्ना जी से चर्चा नही हुई।

आज लोक और तंत्र के बीच दूरी घटाने का हर प्रयास असंभव दिखता है और है भी । यही मानकर हम लोक संसद जैसे मुद्दे तक नीचे उतर गये हैं।हम जानते हैं कि लोकसंसद स्वंय में व्यवस्था परिर्वतन नही है न ही यह कोई मार्ग है। मेरे विचार में यदि कोई और संभव मार्ग दिखता हो तो बताइये। मैं करने को तैयार हूँ। नही तो ऑख मूंदकर बिना विचारे लोक संसद के पक्ष में जनमत बनाना शुरु कर दीजिये।

मुझे अन्ना जी की नीयत पर भी विश्वास है और नीतियों पर भी। किन्तु अन्ना जी को अरविन्द सरीखा साथी नहीं मिल सकता। अन्ना जी अकेले थे उनके पास सब कुछ था लेकिन जुगाड़ नही था। अरविन्द जी के पास जुगाड़ था,किन्तु विश्वस्नीयता नही थी। अन्ना जी ने झुककर अरविन्द की बात मानी और राइट टू रिकाल ग्राम सभा सशक्तिकरण जैसे व्यवस्था परिर्वतन के मुद्दे छोड़कर लोकपाल पर आ गये । ज्यों ही अरविंन्द जी ने अपना जुगाड़ हटा लिया त्यों ही अन्ना जी भी अकेले हो गये और अरविन्द जी की विश्वसनीयता चली गयी। अब दोंनो ही एक बीते समय की बात हो चुके है फिर भी दोंनो ही अभी अन्य लोगो से अधिक विश्वास योग्य दिखते है। इसीलिए हम लोग दोनों को समर्थन और सहयोग कर रहें है। सहभागिता न किसी के साथ पहले थी न अब है। भष्टाचार कोई समस्या नही है कि इसका समाधान खोजा जाय । जब तक सत्ता केन्द्रित रहेगी और लोकतंत्र रहेगा तब तक भ्रष्टाचार इसी तरह चलता रहेगा और भ्रष्टाचार के नाम पर अनेक तथा कथित समाज सेंवियों को दुकानदारी भी चलती रहेगी। भ्रष्टाचार दूर होगा परिवारों" को गॉवों को अधिकार सौंपने से तथा अधिक से अधिक निजीकरण से इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार दूर करने का कोई अन्य मार्ग नही है। यहो कारण है, कि मैं भ्रष्टाचार –भ्रष्टाचार चिल्लाने वालो से कभी प्रभावित नही होता।

संसद या विधान सभा में अच्छे लोगो को भेजने की मुहिम बेमतलब है, अच्छे लोग तानाशाह भी हो सकते है, अच्छे लोगो का पहुँचना भी असंभव है। अच्छे व्यक्ति आसानी से ठगे जा सकते है। स्वतंत्रता के समय संसद में अच्छे लोगो के होते हुए भी उनका प्रतिशत लगातार कम होता गया। फिर भी यदि कुछ ना समझ अच्छे लोगो को चुनने को रट लगाते है। उसमें मैं क्या करु। अच्छे लोग जाकर सदि सत्ता को विकेन्द्रीत ना करें तो मेरे विचार से अच्छे लोगों को रट छोंड़कर विकेन्द्रीयकरण के एकमात्र मुद्दे पर जोर दिया जाये। बुरे लोग भी जाकर यदि सत्ता विकेन्द्रित कर देगें तो हमारी समस्या हल हो जायेगी।" यह सच है कि अम्बेडकर जी को खुश करने के लिए संविधान में दस वर्षो का आरक्षण किया गया था। इसे उस समय भी सब लोग गलत मानते थे। आरक्षण को दस वर्ष से आगे बढ़ाना पुरी तरह संविधान का उलंघन है। संसद को

संविधान संसोधन के अधिकार यह सोचकर दिये गये थे कि उसके दैनिक कियाकलापों में कोई यदि बाधा हो तो संसद उस बाधा को स्वयं दूर कर ल। उसका उद्देश्य कदापि यह नही था कि संसद संविधान की मूल भावना के ही विपरित चली जाय ।आरक्षण को बढ़ाकर संसद नें संविधान की मूल भावना का उलंघन किया है और लगातार यह प्रक्रिया जारी है। सब प्रकार के आरक्षण चाहे कोई भी आरक्षण क्यों न हो समाप्त होने चाहिए ।

वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था राइट टू रिकाल अथवा परिवारों तथा गॉवों को अधिकार सम्पन्न बनाने को बात न मान रही है न मानेगी। यही कारण है कि हमने और मॉगों को छोड़कर केवल लोक संसद से शुरुवात को है। यदि लोक संसद के मुद्दे पर कोई सफलता मिल गयी तो आगे के मार्ग स्वंय मेव खुल जायेगे।

(4) श्री सत्यपाल शर्मा ,बरेली ,उत्तरप्रदेश

प्रश्न– आपने ज्ञान तत्व पाक्षिक के अंक 1 से 15 अप्रेल 2013 मे वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक योग्य प्रधानमंत्री बताया है जो असत्य और तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि श्री मनमोहन सिंह अदूरदर्शी अक्षम और राष्ट्रीय धन का दुरूपयोग कराने मे सहायक प्रधानमंत्री है। कागजो की आकडेबाजी और गठबधन सरकार चलान मे वह अवश्य निपुण है। राष्ट्रीय धन का घोर अपन्यय हो रहा है। विचौलिये मालामाल हो रहे है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री मे इतना साहस नही है कि किसी जगह जाकर औचक निरीक्षण करके केन्द्रिय योजनाओ की स्थिति का स्वयं अवलोकन कर सके। हर जगह माफिया तंत्र भ्रष्टाचार अनाचार हावी है। देश मे लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रथम श्रेय न्यायपालिका को तथा दूसरा श्रेय मीडिया को है।

उत्तर–मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक योग्य प्रधानमंत्री बताया है। जो आपके सोचने के अनुसार असत्य है, क्याकि आप केन्द्रित शासन प्रणाली के पक्षधर है जिसमें प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान के रुप में कार्य करता है तथा मंत्रीमंड़ल उसका सलाहकार होता है जबकि मेरे विचार में यह स्थिति लोकतंत्र के विपरोत है। लोकतंत्र में मंत्रिमंड़ल प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रधानमत्री प्रत्येक मंत्री से उपर होता है, किन्तु मंत्रीमड़ल प्रधानमंत्री से उपर होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री नीति निर्धारण तक सीमित होता है । कार्यान्वयन कार्यपालिका का काम है मंत्री मंडल या प्रधानमंत्री का नही। आज पश्चिम के देशों के लोकतंत्र में भी प्रधानमंत्री मंत्रीमंड़ल स उपर है तो यह स्थिति सुधारने योग्य है न कि अनुकरण करने योग्य । यदि कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे मंत्रीमंड़ल को है" न कि प्रधानमंत्री को दूसरी ओर मनमोहन सिंह जी की दुहरी भूमिका भी है। उन्ह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गॉधी से भी तालमेल बनाकर चलना पड़ता है और आप के अनुसार भी मनमोहन सिंह में यह गुण है। मनरेगा को आपने आलोचना की है यह गलत है। जिस तरह सरकार के अन्य विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे अधिक भ्रष्टाचार मनरेगा में नही है। टूजी का भ्रष्टाचार या कोयले का भ्रष्टाचार मनरेगा स कही ज्यादा है। आपने सुप्रोम कोट की तारोफ की है। तो आप को पता होना चाहिए कि मिड डे मिल का आदेश सुप्रिम कोर्ट का ही दिया हुआ था जिसके दुष्परिणाम आप देख रहे है। मिड डे मिल को जगह नगद ही पैसा देना चाहिए था। यह भी विचार करिये कि सुप्रीम कोट तभी से मजबत होना शुरू हुआ है जबसे प्रधानमंत्री कमजोर हुए है और सरकार मे भी उतनी मजबूती नही रही है। मजबूत प्रधानमंत्रियो के समय मे सुप्रीम कोट लगातार कमजोर हो रहा था । यह भी मनमोहन सिंह की ही देन है कि सुप्रीम कोट मजबूत हुआ।

आप ने बढ़ती हुयी महॅगाइ का जिक किया जो पूरी तरह असत्य है। महॅगाई लगातार घटी है। घट रही है।और आगें भी घटती जायेगी।महॅगाई के घटने का प्रभाव है कि आम लोगो का जीवन स्तर सुधर रहा है। एक सवक्षण हुआ है। जिसके अनुसार चालोस करोंड़ गरोब लोगो के जीवन स्तर में आसत दोगने की वृद्धि हुई है। चालोस करोंड़ मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में औसत आठ गुने की वृद्धि हई है। और चालोस करोंड़ उच्च स्तर के लोगों में औसत चौसठ गुने की वृद्धि हुयी है। मध्यम क्लास महॅगाई –महॅगाई चिल्लाकर गरोब वर्ग की सुविधायें नही बढ़ने देने चाहता जब कि उसका जीवन स्तर गरोब से कई गुना उॅचा है। यह सर्वेक्षण स्वतंत्रता के बाद से अब तक का है। यदि आपको इसमें कोई बात असत्य दिखती हो तो आप प्रश्न करें। मनमोहन सिंह जी के आने के बाद गरिब लोगो के जीवन स्तर में भी अधिक वृद्धि हुई है। यदि भारत में आर्थिक समस्याओ के कारण किसी समूह ने अधिक आत्महत्या को है तो वह किसान ही है। आप सरोखे बीच वाले लोग महॅगाई –महॅगाई चिल्लाकर किसानो के उत्पादन का दाम भी नही बढ़नें देते । टमाटर महॅगा हो जाय तो आपके घर का बजट बिगड़ जाता है। जबकि टी0 बी0,फ्रिज, कुलर या केदारनाथ को यात्रा करने से आपके घर का बजट नही बिगड़ता । अब वह जमाना नही है कि प्रधानमंत्री स्वय चलके किसी काम का निरोक्षण करेगा। पुराने प्रधानमंत्रियों को तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसे नाटक करने पड़ते थे । वे तो कभी –कभी गरोब के गन्दें बच्चे को गोद में लने का नाटक भी करते थे या कभी गरीब के घर का भोजन भी चख लेते थे। आज भी कई लोग साइकिल या बैलगाडी की सवारी का नाटक करते है। मनमोहन सिंह को ऐसे नाटक करने की कोई आवश्यकता भी नही है और करते भी नही है। क्योकि वे प्रधानमंत्री है। देश के मुखिया नही ,मालिक नही कोई तानाशाह नही । मैं फिर कहता हूॅकि मनमोहन सिंह ने भारत में आदर्श लोकतंत्र को मजबूत किया है।साठ

वर्षो से अनेक प्रधानमंत्रियों ने न्यायपालिका को जकड़ कर रखा था मनमोहन सिंह के आने के बाद न्यायपालिका भी स्वतंत्र वातावरण में सॉस ले रही है। इसी तरह की और भी लोकतांत्रिक ' शक्तियॉ मजबूत हो रही है। यह कोई मनमोहन सिंह को साधारण उपलब्धि नही है। आपने मीडिया की बात करके मुझे और भी चौका दिया है। आज कल तो मीडिया एक समाचार को छिपाने के लिये सौ सौ करोड की सौदेबाजी तक कर रहा ह।

5 राज नारायण चौधरी , 30 चित्रगुप्त मार्ग, लालपुरा मुहल्ला, शाजापुर म0प्र0 465001

प्रश्न– ज्ञान तत्व पाक्षिक निरंतर मिल रहा है। तदर्थ हार्दिक धन्यवाद। रिटायर्ड हूॅ आयु के आठ दशक पूरे हो चुके है। इसलिये चाहते हुए भी कुछ न कर पाने का मलाल मन मे रहता है। मेरी इच्छानुसार आप विभिन्न विचार धारा के लोगो को समाहित करने का महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य कर रहे है। इसे अपने संपर्क मे आने वालो तक पहुंचाने का युक्तियुक्त सहयोग मै भी अवश्य करता रहता हूॅ। नये दूरस्थ दो पाठको के नाम पते इस प्रकार है जो ज्ञान तत्व से लाभान्वित होना चाहेंगे। 1 अविनाश चंद्र माथुर, चंद्र शेखर आजाद कालोनी खुरई रोड पो0–बीना जिला सागर म0प्र0, 470113, 2 धीरेन्द्र जैन रिटायर्ड शिक्षक पो0–अकोदिया जिला–शाजापुर म0प्र0, 465223, कुछ आर्थिक सहायता यथा सुविधा शीघ्र ही अवश्य करना चाहता हो। फिलहाल केवल 100 रूपये सहायक सदस्यता शुल्क मो0 न0–068675130, 3090036721 , 09/13/2013 शाजापुर से प्रेषित है। एक सुझाव यह है कि ज्ञान तत्व पाक्षिक प्रत्येक पत्रिका मे स्वैच्छिक सहायता सदस्यता शुंल्क 100 रूपया अंकित होना चाहिये।

आपकी संपर्क यात्राा सफल हो इस कार्यक्रम को देखकर आध्यात्मिक चिंतक आचार्य विनोबा जी की पदयात्रा सहसा याद आ गई। ज्ञान तत्व और संपर्क यात्रा के माध्यम से राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति जनता मे दायित्व बोध जगाने का निरंतर प्रयास होना चाहिये। ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। ,

ज्ञान तत्व 261 मे ज्वलंत सामाजिक प्रश्न देहलो गैग रेप पर विस्तृत चर्चा की गइ ह किन्तु इस विकट समस्या को बढावा देने वाले संमलैगिक विग्रह विधेयक तथा बढते हुए विलासिता के ग्लैमरस यूथ फेस्टीवल और नये नये नशीले प्रदार्थो के अत्याधिक प्रचार प्रसार पर किसी का ध्यान नही जा रहा है। यह राष्ट्रोय चिन्ता का विषय है।

उत्तर–आप का सुझाव है कि ज्ञान तत्व का स्वैच्छिक शुल्क 100 रुपये घोषित कर दिया जाय। यह ठोक नही है। मैं वानप्रस्थो हूॅ और मुझे इस प्रकार के प्रयत्नों से बचना चाहिए । दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान तत्व को अनेक लोग सहायतार्थ हजार रुपये वार्षीक देते है।कुछ गिन चुने लोग तो दस हजार रुपया वार्षिक भी देते है। हमें पैसे को कोई कठिनाई नही हो रही है। हम यह भी जानते है कि वैश्य प्रवृत्ति के लोगो के लिए हजार रुपये वार्षिक अधिक नही है तथा ब्राम्हण प्रवृत्ति वालो के लिए 100 रुपया वार्षिक भी ज्यादा है। जबकि ज्ञान तत्व पढ़ने वालो म ब्राम्हण प्रवृत्ति वाले लोगो को संख्या अधिक है। क्योकि यह वैचारिक पत्रिका है न कि साहित्यक है, न कि राजनैतिक है, न कि व्यावसायिक है। यदि हम 100 रुपया लिखना शुरु कर देंगे तो जो व्यक्ति 100 रुपया देने को स्थिति में नही होगा उसे अपराध बोध होगा।जो हमारे लिये उचित नही होगा। संपर्क यात्रा में हमारे कुछ साथी गये थ । उस यात्रा को लगभग एक वर्ष पूरा हो गया है। हमारी अगली यात्रा लोक स्वराज्य यात्रा होगी जिसका मुख्य विषय लोक संसद होगा।यह यात्रा व्यवस्था परिवर्तन मंच तथा लोक स्वराज्य मंच के बैनर तले होगी । जिनके आग्रह पर मैं भी यात्रा में साथ हूॅ।यात्रा की तैयारी पर चर्चा करने के लिए तीस और इक्तीस अगस्त दो हजार तेरह को नोयडा सेक्टर तैतीस प्रकाश हॉस्पिटल स्कान मंदिर के बीच अग्रसेन भवन में रखी गयी है।आप भी आ सके तो अच्छा होगा। आधामार्ग व्यय आयोजन समिति वहन करेगी। बिनोवा जी की पग यात्रा का स्वरुप क्या था,उद्देश्य क्या था,मैं नही कह सकता। हिन्दी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए मैं ज्ञान तत्व के माध्यम से जो कर रहा हूॅ उससे अधिक करना मेरे लिए न उचित है न संभव है।

ज्ञान तत्व 261 में दिल्ली गैंग रेप पर विस्तृत चर्चा को गयी है।आप के कथनानुसार लिभ इन रिलेशनशिप, समलैंगिक सेंक्स, विलासिता की गलैमर, यूथ फेस्टिवल तथा नये–नये नशीले पदार्थो के अत्यधिक प्रचार –प्रसार " को चिंता का विषय माना है। और सरकार को इस पर ध्यान देने की अपनी सदिच्छा जतायी है। मेरे विचार में हर शिथिल इद्रिय वृध्द जिनकी सेक्स की इच्छाएं मर चुकी है, वे ऐसी बातें अधिक करते है। क्योंकि उनकी युवावस्था में और आज की युवा अवस्था में कितना अन्तर हो चुका है। यह उनको पता नही है।सेक्स एक प्राकृतिक भूख है। जिसे अनुशासन से कुछ नियंत्रित किया जा सकता है।शासन से बिल्कुल नही। सरकार को बलात्कार छोड़कर सेक्स से संबंधित सभी प्रकार के कानूनो से अलग हो जाना चाहिए। तथा अनुशासन का कार्य परिवार या समाज व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए।यदि इससे विकृतियॉ बढ़गी तो दूसरी ओर अपराध भी बहुत घट जायेंगे। अब तक सरकार की या समाज को यह इच्छा साफ नही हुयी है कि वह महिला और पुरुष रुपी दो विपरोत सेक्स कर्मियों के बीच की दूरी घटाना चाहती है या बढ़ाना । मेरे विचार में यह निर्णय व्यक्तियों और परिवारों पर छोड़ देना चाहिए।श्री जगदोश गॉधी लखनउ के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री है। उन्होने पत्र लिखा है कि स्कूलो में सेक्स संबंधित शिक्षा शुरु

नही को जानी चाहिए । उनके अनुसार ऐसा होने से कोमल हद्य बच्चों पर विपरोत प्रभाव पड़ेगा। यह बात सही है कि इस प्रकार की शिक्षा से कामुक प्रवृत्तियॉ बढ़ेगी । साथ ही यह बात भी सही है कि स्त्री और पुरुष के बीच दूरी लगातार घटते जाने से भी कामुक प्रवृत्तियॉ बढ़ेगी जिनका दुष्परिणाम होगा। यदि यह दूरी घटते जाना आज समाज की आवश्यकता है,तो सेक्स की शिक्षा देना नुकसान देह नही होगा। यदि कामुक इच्छाओं को बढ़ते जाने पर नियंत्रण करना हो तब महिला और पुरुष के बीच दूरी बनान की योजनाये भी बनानी पडगी । इस मामले में समाज जितना आगे तक जा चुका है। उसमें किसी एक ओर निर्णय करना कठिन है। अतः यह निर्णय बालिग स्त्री पुरुषों तथा परिवार पर छोड़ देना चाहिए कि वे किस लाइन पर जाना चाहते है।सरकार को स्त्री पुरुष संबंधों के विषय में बने हुए सारे कानुन हटा लेने चाहिए क्योंकि ये कानुन ही अस्पष्ट है दुविधा जनक है, समाधान की जगह समस्याए पैदा करने वाले है।

(6) योगिन गुर्जर 471 जी साखर पेढ सोलापुर ,महाराष्ट्र।

प्रश्न– भारत सरकार ने एक से पचीस पैसे तक की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया दूसरी ओर अनेक वस्तुओं के मूल्य एक नये पैसे तक प्रचलित हैं। पेट्रोल प्रायः एक लीटर भरवाते हैं तो उस समय आमतौर पर दस बीस पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। प्रायः उपभोक्ता ठगा जाता है। सरकार पैसे तक का मूल्य निर्धारण बन्द कर दे या छोटे सिक्के चालू करे।

उत्तर–सच्चाई यह हे कि सन् सैंतालिस का एक पैसा आज पचहत्तर पैसे के समतुल्य है। दो हजार सत्रह अठारह तक वह सौ पैसे के बराबर हो जायेगा तब पचास पैसे भी बन्द हो जायेंगे। यदि सत्तर रुपया अठहत्तर पैसे का पेट्रोल इकहत्तर रुपया कर दिया जायगा तो पचीस लीटर पेट्रोल खरीदने वाले उपभोक्ता को कितना नुकसान होगा। यदि टाफी चाकलेट भी रोंक दे तो आपको आधा मिलना भी बन्द जायगा।ऐसी समस्याऍ समस्या तों हैं जिनका कोई समाधान नही है। यदि आपको कोई समाधान दिखे तो लिखियेगा। भले ही पचास पैसा छपता है किन्तु चलन से लगभग बाहर है। अतः मेरे विचार में यह प्रश्न मेरे लिये अनुत्तरित ही है।

7 आचार्य पंकज राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच

प्रश्न–सत्ता हस्तातरण का सच आपको समीक्षार्थ भेज रहाहूँ। जिसमे भारतीय समाज को बौद्धिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ट्रान्सफर आप पावर के दस्तावेजो मे भी कई स्पष्ट संकेत है कि नेहरू ने ब्रिटिश पक्ष के साथ निम्नांकित बिन्दुओ पर पूर्ण सहमति जताई थी।

1 नेता जी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी माना जायेगा और उन्ह मिलते ही इंग्लैड को युद्ध अपराधी के रूप मे सौप दिया जायगा।

2 दो हजार इक्कीस आजाद हिन्द फौज और उसके अधिकारियों पर चले मकदमे के विषय मे शासन स्तर पर कोई भी सार्वजनिक प्रसारण नही किया जायेगा। सूचना भी नही दी जायगी। और उसके तथ्यो का सार्वजनिक प्रसारण नही किया जायेगा।

3 भारत ब्रिटिश कामन वेल्थ संयुक्त संपदा का अभिन्न अंग बना रहेगा। इस प्रकार भारतीय संपदा पर आपचारिक तौर पर बिटिश स्वामित्व आंशिक रूप से स्वीकार होगा।

4 भारत मे ईसाइ मिशनरियों को धर्मान्तरण की भरपूर सुविधा सुलभ कराई जायगी और गांधी के इस आग्रह का बिल्कुल भी पालन नही किया गया कि धर्मान्तरण हलाहल विष है। और स्वाधीन भारत सरकार उसे पूरी तरह गैर कानूनी करार देगी।

5 भारत मे सभी ब्रिटिश कानून यथावत जारी रहेंगे। स्वाधीन भारत की संसद उन सब कानूनों को वैधता प्रदान करेगी। इसकी जिम्मेदारी नेहरू लेते है।

6 भारत मे अंग्रेजो को पूर्ण महत्व प्राप्त होगा और ब्रिटिश शिक्षा और ब्रिटिश ज्ञान कोष से भारतीय शिक्षित समाज को सदा संबंद्ध रखा जायगा।

7 ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के लिये एक माडल के रूप मे मान्य होगी।

इस इन सब सहमतियो के बीच सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया और नेतृत्व का निर्धारण हुआ । इतिहास के इन तथ्यों को सार्वजनिक विमर्श का अंग बनाया जाना जरूरी है। नेहरू ने सत्ता संभालने के बाद इतिहास के इन तथ्यों को सार्वजनिक चर्चा से बाहर रखने की प्रेरणा दी।

उत्तर– आप ने सत्ता हस्तान्तरण के समय का जो विवरण भेजा है वह ऐतिहासिक घटना अवश्य है किन्तु मेरी जानकारी में नही है। यही कारण है कि मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी करने से असमर्थ हूँ। यदि आप इस संबंध में और जानकारी भेजेंगे तो ज्ञान तत्व उन्हे जनहित को सामग्री मानकर प्रकाशित करने में कोई संकोच नही करेगा।

8 गरीबी रेखा का खतरनाक खेल– विस्फोट डांट काम से ।

विचार–हर आम आदमी के लिये शहर मे 33 और गांव मे 27 रूपये रोजाना की जरूरतो के लिहाज से पर्याप्त बताने पर केन्द्र सरकार की हर ओर आलोचना हो रही है। हांलाकि ऐसा कहकर सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीनेवालों की संख्या घटाकर अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन गरीबी घटाने के नाम पर क्या केंन्द्र सरकार कोई खतरनाक खेल खेल रही है जो अभी जनता को समझ मे नही आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डा0 मुरली मनोहर जोशी ने आज नई दिल्ली मे मीडियां से बात करते हुए यही कहा कि नयी गरीबी रेखा निर्धारित करके कांग्रेस की केन्द्र सरकार खतरनाक खेल कर रही हे जो खाद्य सुरक्षा विधेयक से जुडा हुआ है।

डा0 जोशी का कहना है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत केन्द्र की कांग्रेस सरकार गरीबी घटाने का यह खेल कर रही हे। उन्होने बताया कि नये मानको के अनुसार गरीबो का आकडा 21 प्रतिशत पर लाकर सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केन्द्र द्वारा खर्च किये जाने वाले धन पर संभावित सवालो को खत्म कर देना चाहती है। उन्होने कहा कि सरकार जितना कम गरीबो की संख्या बतायेगी उसकी योजना का खर्च उतना कम आयेगा। लेकिन क्योकि वास्तव मे गरीबो की संख्या मे कोई कमी नही आइ है लिहाजा गरीबी का अतिरिक्त भार राज्य सरकारो पर पडेगा। उन्होने कहा कि केन्द्र द्वारा प्रस्तुत यह आकडा राज्य सरकार की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता है। लिहाजा राज्यों मे जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग है उनको खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत अपने पास से धन खर्च करना होगा। डा0 जोशी ने कहा कि गरीबो की संख्या मे कमी का ऐलान देश को गुमराह करने के लिये और खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत राज्य सरकारों पर अनावश्यक बोझ डालने के लिये किया जा रहा है। डा0 जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार देश मे गरीबों की संख्या मे कमी का ऐलान करके यह कहना चाहती है कि देश की अर्थ ब्यवस्था सुधर रही है। डा0 जोशी ने कहा कि यह सरकार की सोची समझी गहरी नीति है जिससे वे एक तरफ खाद्य सुरक्षा विधेयक भी पास करवा लेना चाहते है तो दूसरी तरफ विकास का श्रेय भी ले लेना चाहते है।

डा0 जोशी ने गरीबी रेखा के निर्धारण पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण कर लिया है जो न सिर्फ देश के गरीबो का मजाक है बल्कि ऐसा करके कांग्रेस सरकार ने देश की जनता को भी गुमराह किया है।

उत्तर– आप भारतीय जनता पार्टी में एक विश्वसनीय विचारक के रूप में माने जाते है। हमे यह विश्वास है कि दल हित मे आप सत्य को भले ही छिपा ले किन्तु झूठ तो नही बोलेगे । सरकार ने जो गरीबी रेखा तय की है उसकी आप द्वारा आलोचना सुनकर हमारे इस विश्वास को धक्का लगा है। पूरे देश में सभी दलो तथा सभी विचारको की ओर से इस गरीबी रेखा की एक स्वर में आलोचना हुयी है। यहॉ तक कि कांग्रेस के लोग भी निरूत्तर दिखते है किन्तु मै समझ नही पा रहा कि सत्य क्यो छुपाया जा रहा है? क्यो झूठ बोला जा रहा है?।विशेष कर कांग्रेस की ओर से ऐसा क्यो हा रहा है?

मैने बहुत सोचा कि गरीबी रेखा अटल सरकार के टाइम मे 12 रूपये ग्रामिण तथा 18 रूपये शहरी लोगो के लिए निर्धारित थी। दस वर्षो बाद मनमोहन सिह सरकार ने 12 रूपये को बढा कर 28 रूपये तथा 18 को बढा कर 33 रूपये किया है।यह तो महगाई क हिसाब से दस वर्ष पूर्व के मूल्य का पूनः निर्धारण मात्र है। इसमे न कोई रेखा बदलो है, न कोई मापदण्ड बदला है। फिर पता नही क्यो सरकार इस सोधी बात को छिपा रही है? साथ ही यह भी समझ मे नही आ रहा कि आप जैसा विद्वान अटल सरकार के समय की गरीबी रेखा से तुलना क्यो नही कर रहा। दस वर्ष पूर्व की गरीबी रेखा और आज की गरीबी रेखा तो एक ही है। उस समय की अपेक्षा आज आम नागरीको का जोवन स्तर सुधरा है। यह भी स्पष्ट है कि गरीबो की संख्या घटी है। फिर इस सच्चाई को छिपाने का क्या अर्थ है? चाहे सरकार किसी की रही हो किन्तु गरीबो रेखा का मापदण्ड प्रतिव्यक्ति ग्रामोण इलाके का 2400 कैलोरी और शहरी इलाके मे 2100 कैलोरी का है । समय समय पर रूपये के गिरते मूल्य के आधार पर रूपये मे उसका माप दण्ड बदलता है परन्तु कैलोरी का मापदण्ड स्थिर रहता है।आज भी मापदण्ड वही है और महगाई के आधार पर औसत 16 की जगह 30 रूपये के आस पास तय किया गया है तो इसमे गलत क्या है।

प्रश्न यह भी उठता है कि जब 30 रूप्ये के माप दण्ड मे ही गरीबो की संख्या 21 करोड है तो हम क्यो न पहले इसी संख्या को शून्य तक ले आवे। इस संख्या को पहले शून्य करने की अपेक्षा माप दण्ड बढाकर इस संख्या को बढाने का प्रयास वास्तविक गरीबो के प्रति छल तो नही है? आप ने अपनी सरकार के कार्यकाल मे भी इस संख्या को शून्य करने का कोई प्रयास नही किया।

छत्तीसगढ सरकार ने धोषणा कर रखी है कि हमारे पूरे प्रदेश मे प्रत्येक शहर मे होटल मे 5 रूपये में भरपेट खाना मिलेगा और यह खाना मिलता भी है।मै नही समझा कि भाजपा के लोग इस 5 रूपये और 12 रूपये के भरपेट भोजन के विवाद में क्यो पडे है। यदि सरकार चाहे तो 10 रूपये मे भरपेट भोजन होटल से मिल सकता है। क्योकि उस होटल वाले को सरकार सस्ते मूल्य पर अनाज देती है। फिर इस बहस का क्या मतलब है? यदि कोई गरीब व्यक्ति बाजार से भी अनाज खरीद कर अपने घर मे भाजन बनावे तो वह वर्तमान समय मे 14 रूपये प्रति व्यक्ति से कम पडता है जिसमे रोटी चावल दाल और सब्जी

सामिल है।फिर मै नही समझा कि इतना विरोध किस बात का है? मै यह भी नही समझा कि कांग्रेस के लोग सच्चाई को क्यो छिपा रहे है? आज चावल का भाव 18 से 19 रूपये प्रति किलो हमारे छेत्र मे है । गांवो मे तो यह भाव और भी कम है। यदि सरकारी सस्ते अनाज का मूल्य जोडा जाय तब तो यह खाना 5 से 6 रूपये के आस पास ही पडेगा। किन्तु बाजार दर मे भी खरीदने पर 14 रूपये से कम ही पडता है। मेरे समझ मे नही आया इसलिए मैने यह प्रश्न उठाया क्योकि आप का लेख पढकर मै भ्रम मे पडा अन्यथा अन्य पेशेवर नेता या मिडिया वाले कुछ न कुछ बोलते रहते और उनकी विश्वसनीयता भी नही है।

(9) चितरंजन भारती 132एच0 पीसी टाउन शिप ,पंचग्राम, असम ,788802

प्रश्न–विचार और साहित्य एक दूसरे के पूरक लेख पसंद आया। आपने कुछ निष्कर्ष निकाले है। भारत की लगभग आधी आबादी निरक्षर है। बाकी आधी आबादी का बमुश्किल कुछ प्रतिशत ही साहित्य मे रूचि लेता है। ऐसे मे यह स्वाभाविक है कि साहित्य के माध्यम से विचार अधिक लोगो तक नही पहुंचते । कोरे विचार काफी कडे रूक्ष और शुष्क होते है। ऐसे मे सामान्य जन उसमे रूचि ले नही पाते। इसलिये उन विचारो को साहित्यकार मनोरंजन और घटनाओं की चाशनी मे लपेटकर प्रस्तुत करते है ताकि वह पठनीय और लोकप्रिय हो सके। अज्ञेय के उपन्यासों मे विचार है मगर उसे पढने मे पसीना आ जायगा। जबकि प्रेमचंद्र साहित्य के विचारो को सरलता मे समझा जा सकता है। शायद आपको जानकारी हो कि भारत मे ही नही बल्कि विश्व मे भी साहित्य भी लोकप्रिय और प्रतिष्ठित खानो मे बंटा है। प्रतिष्ठित लेखक लोकप्रिय लेखको को हिकारत की नजर से देखते है, जबकि लोकप्रिय लेखक प्रतिष्ठित लेखकों की दयनीय हालात पर हंसते है।
आपके हिसाब से विचारक को अधिकतम सम्मान तथा साहित्यकार को सामान्य सम्मान मिलना चाहिये। यहां तक तो ठीक है। मगर यह कहना कि विचारक को न्यूनतम सुविधाएं और साहित्यकार को सामान्य सुविधाएं मिलती है ठीक नही है। सुविधाभोगी साहित्यकारों की तरफ आप नजर दौडाए तो पता चलेगा कि वे या तो पत्रकारिता से जुडे थे अथवा किसी बडी नौकरी से या वे विरासती अमीर थे। इसलिये उनका अपना एक आभा मंडल है। स्वतंत्रता पूर्व स्थिति तो और खराब थी। भारतेन्दु हरिश्चंद्र प्रेमचंद्र , प्रसाद से लेकर निराला तक फाकाकशी ही करते रह गये।
साहित्य और विचार के इस जुलगबंदी मे विचार पर दबाव बढ रहा है और इस अभिव्यक्ति पर आये संकट का सामना करने के आवाहन का आपने स्तुत्य प्रयास किया है।

उत्तर––मेरे कहने का आशय यह है कि विचारक आमतौर पर प्रवत्ति से ब्राहम्ण के समान माना जाता है और साहित्यकार प्रवृत्ति मे वैश्य के समान माना जाता है। विचारक को अपने सम्मान से सन्तुष्ट होना चाहिए । यदि साहित्यकार को सुविधायें अधिक मिलती है तो विचारक को उससे दुखी या चिन्तित नही होना चाहिए। क्योंकि धन अथवा सुख सुविधायें भले ही साहित्यकार को अधिक है, किन्तु सम्मान के मामले में वह विचारक से नीचे ही रहेगा। आपने भी इस बात को ठीक से समझा है मेरे लिए यह संतोष की बात है।

(10) श्री पी0 एन0 मेन्डोला, जी 144 उदय पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान 302019

विचार––आपके चिन्तन और विचार की बुकलेट ज्ञान तत्व प्राप्त होती रही है। आपके विचार कि संसद एक जेल खाना है तथा संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र मे बदलना ही होगा। यह एक मूल प्रश्न है। क्या सहभागी लोकतंत्र संभव है? हमारा विश्लेषण है कि पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र मे सहभागी लोकतंत्र संभव नही है। सांराश प्रस्तुत है।

संसदीय लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र की एक शाखा है, एक दर्शन है, संसदीय लोकतंत्र को समझने के लिये पूंजीवाद की परिभाषा पर यदि हम विचार कर ले तो उपयुक्त होगा।

पूंजीवाद की मूल अवधारणा

व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता तथा उससे स्वैच्छिक उपभोग का व्यक्तिगत अधिकार पूंजीवाद का प्रचलित सिद्धात तथा इसकी आस्था का केन्द्र बिन्दु है। आस्था का यह केन्द्र बिन्दु इस मान्यता पर आधारित है कि व्यापक सामान्य कानून कें अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उसके लिये अपने दृढ प्रयास से अन्ततः एक उदार सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा।

पूंजी संचय

मुख्य मुद्दा यह नही है कि पूंजी का संचय अनुचित है क्योकि पूंजी प्रगति का एक आवश्यक तत्व है बल्कि प्रश्न यह है कि इसका मालिक कौन हैं? किसका इस पर नियंत्रण है और किसके लाभ के लिये इसका प्रयोग किया जायेगा? यही वह मुख्य बिन्दु है जिस पर नागरिको ं का घ्यान जाना चाहिये, चर्चा बहस का बिन्दु बनना चाहिये। –लेखक फलेक्स ग्रीन

महोदय विश्व पूंजीवाद का कनिष्ठ सहयोगी भारतीय पूंजीवाद है, 15 अगस्त 1947 को ही भारत मे पूंजीवाद की स्थापना हो गई थी । पूंजीवादी लोकतंत्र मे राजनैतिक दलो का गठन उनकी कार्यप्रणाली प्रोग्राम एजेण्डा उनके नेताओ सदस्यो द्वारा संचालित नही होते है अपितु उन समूहो गठजोडों प्रतिष्ठानो राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितो के अनुरूप ही संचालित होते है। साधारण भाषा मे आर्थिक शक्ति के ये केन्द्र ही सत्ता का संचालन तथा नीतियों निर्धारित करते है। ये समूह प्रचार प्रसार के लिये आर्थिक अनुदान दलो के संचालन के लिये, हर माह आर्थिक सहयोग, करोडो मे मुहैया करवाते है। समाज को बांटने के लिये धर्मगुरूओ को पैदा करते ह जन प्रतिनिधि कथा कथित धर्म गुरूओ के चौखट पर हाजरी लगाते रहते है। तथा कथित धर्म गुरूओ का लालन पालन इन शक्ति केन्द्रो की आवश्यकता है। समाचार माध्यमो पर प्रभावी नियंत्रण व शिक्षा व्यवस्था को तर्क ज्ञान विज्ञान पर आधारित करने का विरोध करते हुए शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे नौकरी दे ऐसी एक खास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक बनावट इनका लक्ष्य होता है। उसी मे इधर उधर कुछ पैबंद लगाने को यह समूह समर्थन भी करते है । ऐसी स्थिति जो भारत मे बदा दी गई सहभागी लोकतंत्र के लिये उर्जा संसाधन मैन पावर कहा व कैसे उपलब्ध होगी यह मूल प्रश्न है।

पूंजीवाद के ढाचे व सोचने मे गठित होने वाला नया पुराना राजनैतिक दल बहुत लम्बे समय तक सहभागी लोकतंत्र के लिये काम नही कर सकता। व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार जिसे भारतीय दर्शन मे माया, लोभ लालच व्यक्तिगत हित मोह, अहंकार से जाना जाता है, जिसका जाप भारत के धर्मगुरू सर्व साधारण जनता को करा रहे है, यह व्यक्तिगत स्वार्थ ही देर सवेर अपना असर संगठनो मे दिखाता है, संगठनों मे पलोता देता है। इस प्रकार नेता, कार्यकर्ता व्यक्ति गौण व सम्पत्ति के अधिकार का भाव पूंजीवादी व्यवस्था के मूल को प्रभावकारी ढंग से स्थापित भी करता है। वह ऐसे सभी लोगों जो ढांचे मे प्रभावशाली पदो पर है स्थिति मे है, वे व्यक्तिगत हितो के खातिर एकमाला मे स्वतः ही गुथ जाते है। एक दूसरे के हित साधक बन जाते है व पूंजीवाद की परिभाषा के अनुसार व्यापक सामान्य कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ व उसके लिये दृढ प्रयास से अन्ततः एक उदार सामाजिक व्यवस्थ का उदय होगा ऐसा कभी नही होता है। यह पूंजीवाद की इच्छा है, भारत मे केन्द्र व राज्यों मे जो घोटालो की श्रृखला है , उसका आप विश्लेषण करसकते है । घोटालो मे अनेको का व्यक्तिगत हित सम्मिलित है।इसलिये घोटाले रोके नही जा सकते है।

अतः हमारा विश्लेषण है कि उदार सामाजिक व्यवस्था कभी कानून बनाने से नही बनती है । अपित पूंजीवादी शोषण भेदभाव गैर बराबरी विज्ञान व तर्क पर आधारित वैचारिक संघर्ष को केन्द्र कर कुछ नागरिको को मार्क्स भगत सिंह के चिंतन पर काम करते हुए आगे आना होगा। वैचारिक संघर्ष के साथ आम जनता की एकता के लिये अभियान चलाना होगा। न कोई अल्पसंख्यक न बहु संख्यक । हम सिर्फ नागरिक है, स्थापित करना होगा । जाति के प्रश्न का हल तर्क विज्ञान व इतिहास से ढूढना होगा। पूंजीवाद की नागरिको को बांटने की नीति के विपरीत जनता समितियां कालोनी समितियां पंचात समितियां वार्ड संगठन गरीब किसान खेत मजदूरो के संगठन नीति नैतिकता जीवन के हर क्षेत्र के विचारो को केन्द्र कर संघर्ष करने वाले समूहों का निर्माण इन सबका एक शीर्ष मंच क्रान्तिकारी पार्टी की स्थापना के कार्य मे जुटना होगा।

उक्त समितियां ही विकास का प्रस्ताव निर्माण निगरानी भुगतान देखेगी व सर्व साधारण से अनुमोदन करवायेगी । इस प्रकार नौकरशाह ठेकेदार दलाल जन प्रतिनिधि पार्टी गठजोड को परास्त किया जा सकेगा। लूट खसौट बंद होगी। वोट डालना लोकतंत्र नही अपितु नागरिक भागीदारी वाला लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा।

समितियां अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने । पूंजीवादी राजनैतिक दलो के उम्मीदवारो के विरूद्ध वे चुनाव लडे , चुनाव कोष की व्यवस्था जनता समितियां करे, व्यय राशि का विवरण सार्वजतिक हों इस पूरी प्रक्रिया की दो बाधाए हैं जातिवाद का समाधान व अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के विभाजन को रोके बिना प्रक्रिया असंभव सी लगती है। क्योकि जाति समस्त राजनैतिक दलो की खाद का काम कर रही है।

हर मतदाता/नागरिक हर माह अपनी आय का एक अंश इन समितियों को व्यवस्था बदलने पूजीवाद के स्वैच्छिक उपभोग का अधिकार का विरोध करने हेंतु स्वेच्छा से अर्पित करें।

क्या यह कठिन व दुरूह प्रक्रिया संभव है? हमारा उत्तर हां मे है । कुछ को देश के शहरो गांवो कस्बो मे व्यक्तिगत पहल करनी होगी। इस पहल को समूह मे बदलना होगा। ऐसे अनेकों समूह पहल कर सकते है। इसके साथ ही पूंजीवादी पाटियां पुलिस के माध्यम से ऐसे व्यक्तियो मजदूरो सामाजिक कार्यकर्ताओ राजनैतिक कार्यकताओं को फर्जी काउण्टर मे हत्या भी करवा रही है। उनका उत्पीडन भी व्यापक स्तर पर कर रही है, ताकि भागीदारी वाला लाकतंत्र स्थापित न हो सके।

हमारा मानना है कि उक्त प्रक्रिया के तहत ही सहभागी लोकतंत्र संभव है। वर्तमान मे देश का एक भी राजनैतिक दल सहभागी लोकतंत्र चाहता ही नहीं हें वे पूंजीवाद के स्वैच्छिक उपभोग के अधिकार पर अंकुश नही चाहते है। यही कारण है कि आंन्ध्र से लेकर उडीसा तक जो खनन सम्पदा है उसकी लूट व उसका उपभोग किसके लिये हो किन

समूहो का इस खनिज सम्पदा पर नियंत्रण हो । विस्थापन हो या न हो के कारण ही तो राज्य की हिंसा का रूप हम देख रहे है।

उत्तर––आप ने पूँजीवाद और लोकतंत्र को एक साथ जोड़ दिया ह जो उचित नही है,ये दोनों अलग –अलग विचार है जो एक साथ जुड़कर साथ काम करते है। लोकतंत्र ने अपनी सुविधा के लिए पूँजीवाद को जोड़ लिया क्योंकि दूसरी ओर साम्यवाद ने तानाशाही और सरकारीकरण को अपने साथ जोड़ लिया है । यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र होगा तो पूँजी का सरकारीकरण संभव नही है, और तानाशही होगी तो पूँजी का सरकारी करण भी हो सकता है और नही भी । मेरे विचार से सहभागी लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र की आगे की सोढो है। संसदीय लोकतंत्र कहो भी सहभागी लोकतंत्र में बाधक नही है।पूँजीवाद भी सहभागी लोकतंत्र में बाधक नही होगा।यह अवश्य है कि सहभागी लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र और पूँजीवाद का सुधरा हुआ स्वरुप होगा।मैं आप से सहमत हूँ कि वर्तमान लोकतंत्र में अनेक खामियॉ है। जिनकी ओर आपने इशारा किया है। यही कारण है कि हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से इन खामियों को दूर करेंगे । सहभागी लोकतंत्र के लिए हमें भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन करने होंगे। जो वर्तमान पूँजीवादी धर्म गुरुओं से संचालित राजनीति न करेगी न करने देगी।इसके दो भाग है। या तो संसद में जाकर संविधान में व्यापक संसोधन कर दिये जाये। अथवा छोटे–छोटे टूकड़ो में जनमत जागृत करके वर्तमान संसद को ही इस दिशा में कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया जाये हम लोगो ने सहभागी लोकतंत्र का प्रस्तावित संविधान जारी कर दिया है जो ज्ञान तत्व 235,से 237 तक में गया है आप इनकी प्रति kaash india.com website पर निकाल सकते है या हमसे भी मॅगा सकते है। दूसरी दिशा में हम पहले कदम के रुप में लोक संसद के लिए जनमत जागरण कर रहे है संभव है कि कुछ अच्छे नतिजें आयेगें । नये प्रस्तावित संविधान में हमने व्यक्तिगत पूँजी के सिद्धांत को पूरी तरह समाप्त करके परिवार की संपत्ति को मान्यता दी है। संभव है कि इससे कुछ सुधार होगा।आप ने मार्क्स और भगत सिंह के मार्ग की आवश्यकता बतायी है। मार्क्स का सिद्धांत पूरी तरह असफल भी है।और सहभागी लोकतंत्र की सोच के बिलकुल विपरोत भी । भगत सिंह का मार्ग तब उचित हो सकता है जब तानाशही स संघर्ष की आवश्यकता हो और कोई लोकतांत्रिक मार्ग उपलब्ध न हो । मैं नही समझा की वैचारिक ,वैज्ञानिक और तर्क अधारित संघर्ष के लिए ये मार्क्स या भगत सिंह की आवश्यकता क्यों है।

मैं आप से सहमत हूँ कि अल्पसंख्यक बहुँसंख्यक का विचार घातक है। मैं इससे भी सहमत हूँ कि जाति या धर्म के नाम पर संगठनों का बनना भी घातक है। आप किन समितियो की बात कर रहे है उनसे मैं इस तरह सहमत हूँ कि परिवार एक संगठित समिति होगी । एक हजार की आबादी को एक वार्ड या गॉव मान लिया जायेगा। वह भी एक समिति होगी इस तरह समितियॉ उपर तक चली जायेगी । पूँजीवाद को सहभागी लोकतंत्र का शत्रु मानने की आवश्यकता नही है। पूँजीवाद, तो समाजवाद और साम्यवाद का एक विकृत समाधान ह जिसे सहभागी लोकतंत्र के द्वारा ठोक किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण–

मैंने ज्ञान तत्व के अंक 272 में बनकर जी के एक पश्न के उत्तर में यह लिखा था कि डा0 भीमराव अम्बेंड़कर के इस्लाम धर्म ग्रहण करने की बात मैने लिखी थी उसका मेरे पास कोई प्रमाण नही है।मैनें इस अपुष्ट लेखन के प्रति खेद भी व्यक्त किया था।किन्तु मैं इसके लिए विचलित अवश्य था कि मैने कुलदीप नैयर जी जैसे स्थापित विद्वान के कहने पर यह बात लिख दी और प्रमाण नही रखा। मैं कोई इतिहास का जानकार नही हूँ । किन्तु फिर भी मैनें लगातार अम्बेड़कर जी के इस यथार्थ को खोजने को कोशिश की जिसमें मुझे सफलता भी मिली । अम्बेड़कर जी ने 1929 में अपनी पत्रिका बहिष्कृत भारत में इस्लाम ग्रहण करने को बात लिखी है। जिसका गॉधी जी ने भरपूर विरोध किया । जब अम्बेड़कर जी अपनी बात पर अड़े रहे तब गॉधी जी ने अनशन करने को धमकी दी। अम्बेड़कर जी गॉधी जी का सम्मान करते थे । वे इस्लाम न ग्रहण करने हेतु सहमत हुये ,किन्तु हिन्दू धर्म के प्रति उनके मन में कटुता कम नही हई और प्रतिक्रिया स्वरुप वे बौद्ध बने । मैनें पिछले अंक में जो क्षमा प्रार्थना की थी वह मैं वापस लेता हूँ।"

प्रिय बन्धु **दिनांक–16/08/13**

व्यवस्था परिर्वतन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य पंकज, संरक्षक प्रमोद कुमार वात्सल्य तथा लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा बंगलोर, राष्ट्रीय संगठन सचिव रमेश चौबे ने मिलकर संयुक्त रूप से लोक संसद का विचार आगे बढाने के उद्देश्य से दो माह की लोक स्वराज्य यात्रा की योजना बनाई है। दोनो संगठनो के निवेदन पर मैं भी लगभग दो माह तक साथ जाने की स्वीकृति दे चुका हूँ। यात्रा कब से हो कहॉ से हो कहां कहां हो इन सब की योजना बनाने हेतु आप सब

साथियों की एक संयुक्त बैठक तीस तथा इकतीस अगस्त को नोएडा सेक्टर तेतीस अग्रसेन भवन में रखी गई है। यह भवन प्रकाश हास्पिटल तथा इस्कान मंदिर के बीच है। भोजन तथा निवास की ब्यवस्था आयोजको की है। प्रत्येक सहभागी को मार्ग ब्यय का आधा पैसा आयोजन समिति देगी। विशेष आवश्यक होगा तो आयोजन समिति पूरा भी दे सकती है।

इन्हीं दो दिनो में ए टू जेड टी वी चैनल एक एक धंटे के चार विशेष विचार मंथन के कार्यक्रम भी रेकार्ड करेगा जो टी वी पर दिखाया जायगा। यह रेकार्डिग भी उसी जगह होगी।

आप से निवेदन है कि आप बैठक में आने की कृपा करे।

निवेदक
बजरंग मुनि
9617079344
कार्यालय
दीपक जायसवाल
9575566074